भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2126
उत्तर देने की तारीख 04 मार्च, 2020

दार्जिलिंग और कलिंपोंग क्षेत्रों में संचार की समस्या

2126. श्री राजू बिष्टः

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दार्जिलिंग और कलिंपोंग के पहाड़ी लोग मोबाइल और इंटरनेट नेटवर्क में संचार की गंभीर समस्या का सामना करते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) उक्त क्षेत्र में डिजिटल इंडिया का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

संचार, मानव संसाधन विकास तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री
(श्री संजय धोत्रे)

(क) और (ख) दार्जिलिंग और कलिंपोंग जिलों के बसे हुए 616 गावों में से 610 गांव मोबाइल सेवाओं द्वारा कवर किए गए हैं। इनमें से 50 गांव केवल 2जी सेवाओं द्वारा कवर किए गए हैं और शेष गांवों में 3जी/4जी सेवाएं उपलब्ध हैं जिनसे लगभग 99.07% जनसंख्या को कवर किया गया है। दार्जिलिंग और कलिंपोंग जिलों में प्रचालनरत बेस ट्रांसीवर स्टेशनों (बीटीएस) की दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी)-वार संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है। सामान्यतः, 3जी और 4जी मोबाइल बीटीएस द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों में 2जी मोबाइल बीटीएस द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों की तुलना में बेहतर इंटरनेट गति है। मोबाइल इंटरनेट की डाउनलोड/अपलोड गति प्रौद्योगिकी (2जी/3जी/4जी-एलटीई), उपभोक्ता को सेवा प्रदान करने वाले सेल से समीपता, सेल द्वारा सेवा प्राप्त कर रहे प्रयोक्ताओं की संख्या, सेल के परियात (ट्रैफिक), उपभोक्ताओं द्वारा प्रयुक्त प्रयोक्ता उपस्कर/मोबाइल हैंडसेट इत्यादि जैसे अनेक पहलुओं पर निर्धारित होती है। इसके अतिरिक्त, बीएसएनएल 15 एक्सचेंजों से लैण्डलाइन इंटरनेट सेवाएं प्रदान कर रहा है और इंटरनेट सेवाओं में सुधार करने के लिए, 3 एक्सचेंजों के अलावा सभी एक्सचेंजों को एनजीएन में परिवर्तित किया गया है; इन 3 एक्सचेंजों को भी इस वित्त वर्ष तक एनजीएन में

परिवर्तित कर दिया जाएगा। इसके अलावा, मोबाइल कवरेज में सुधार करने के लिए बीएसएनएल द्वारा 76 4जी बीटीएस संस्थापित करने की योजना बनाई गई है।

सरकार ने सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) का उपयोग करके कवर नहीं किए गए सभी गांवों को चरणबद्ध तरीके से कवर करने की योजना बनाई है। सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों, लक्षद्वीपों, हिमालयी राज्यों, पश्चिमी सीमावर्ती राज्यों और बहुत ही महत्वपूर्ण वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों जैसे दूरस्थ क्षेत्रों तक प्रथम चरण में पहुंच बनाने को प्राथमिकता दी है।

भारतनेट परियोजना का कार्यान्वयन देश की सभी ग्राम पंचायतों (लगभग 2,50,000) को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। भारतनेट चरण-I परियोजना के अन्तर्गत दार्जिलिंग और कलिंपोंग क्षेत्रों की 26 ग्राम पंचायतों में से 24 ग्राम पंचायतों को सेवा प्रदायगी के लिए तैयार कर दिया गया है और भारतनेट चरण-II परियोजना के अन्तर्गत 124 ग्राम पंचायतों को कवर करने की योजना बनाई गई है। इस अवसंरचना का उपयोग दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा ग्राम पंचायतों/दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर किया जाएगा।

सरकार ने गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की प्रदायगी के लिए अवसंरचना संवर्धन को सुकर बनाने के लिए अनेक नीतिपरक पहल की हैं। इनमें स्पेक्ट्रम की ट्रेडिंग/शेयरिंग/उदारीकरण, निष्क्रिय एवं सक्रिय अवसंरचना शेयरिंग की अनुमति प्रदान करना, मार्गाधिकार नियमावली, 2016 अधिसूचित करना, टावर संस्थापित करने के लिए सरकारी भूमि/भवनों को उपलब्ध कराना इत्यादि शामिल हैं। दूरसंचार सेवा प्रदाता अपनी तकनीकी-वाणिज्यिक अपेक्षाओं के आधार पर अपनी कवरेज और/अथवा अपने नेटवर्क की क्षमता में सुधार करने के लिए निरंतर आधार पर मोबाइल टावर और बीटीएस भी संस्थापित करते हैं।

अनुबंध-I

"दार्जिलिंग और कलिंपोंग क्षेत्रों में संचार की समस्या" के बारे में माननीय संसद सदस्य श्री राजू बिष्ट द्वारा पूछे गए लोक सभा के दिनांक 04 मार्च, 2020 के अतारांकित प्रश्न सं. 2126 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

दार्जिलिंग और कलिंपोंग जिलों में प्रचालनरत बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) की दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी)-वार संख्या

क्र.सं.	**टीएसपी का नाम**	**प्रचालनरत बीटीएस की संख्या**	
		कलिंपोंग जिला	**दार्जिलिंग जिला**
1	एयरटेल	170	1085
2	आरजियो	151	1198
3	वीआईएल	116	812
4	बीएसएनएल	19	285
	कुल	**456**	**3380**

****